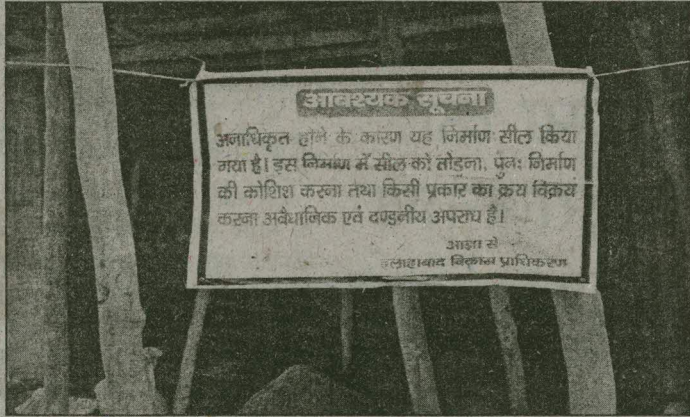


## नैनी और फाफामऊ में एडीए ने सील किये अवैध निर्माण



एडीए द्वारा सील किया गया अवैध निर्माण।

इलाहाबाद ०८ जनवरी। इलाहाबाद विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष देवेन्द्र कुमार पाण्डेय के अवैध निर्माण के सम्बन्ध में दिये गये आदेश में एडीए के जोनल अधिकारियों ने शनिवार को दो अवैध निर्माण को सील किया। एडीए के जोनल अधिकारी पुष्कर श्रीवास्तव ने अरैल क्षेत्र में रमेश महाजन द्वारा किये जा रहे अवैध निर्माण को सील कर दिया वहीं फाफामऊ

क्षेत्र में जोनल अधिकारी ने जोन संख्या ६ में जोनल अधिकारी जय राम मौर्य के नेतृत्व में केबी सिंह एवं सविता सिंह द्वारा किये जा रहे निर्माण को सील कर दिया इस कार्यवाही में जोनल अधिकारी के अलावा अवर अभियन्ता अश्वनी कुमार मिश्र महेश चौधरी अशोक कुमार सिंह क्षेत्रीय सुपरवाइजर एवं एडीए पुलिस बल एवं प्रवर्तन दल के सदस्य मौजूद थे।

पुनाइटेस भारत 8/1/17

## फाफामऊ में अवैध निर्माण किए सील

इलाहाबाद। एडीए ने शनिवार को अवैध निर्माण के खिलाफ अभियान चलाया। इस दौरान नैनी में जोनल अफसर पुष्कर श्रीवास्तव के नेतृत्व में रमेश महाजन का निर्माण सील किया गया।

फाफामऊ शांतिपुरम आवास योजना में जोनल अफसर जयराम मौर्य के नेतृत्व में केडी सिंह और सविता सिंह की ओर से कराए जा रहा निर्माण भी सील कर दिया गया। कार्रवाई में क्षेत्रीय अवर अभियन्ता, क्षेत्रीय सुपरवाइजर और पुलिस बल शामिल रहा।

हिन्दुस्तान 9/1/17

## तीन अवैध निर्माण सील

इलाहाबाद : एडीए के जोनल अधिकारी पुष्कर श्रीवास्तव ने अरैल में रमेश महाजन और जोनल अधिकारी जयराम मौर्य ने शांतिपुरम आवास योजना में केडी सिंह और सविता सिंह द्वारा कराए जा रहे निर्माण को सील कर दिया।

दैनिक जागरण 9/1/17

## संगम टावर में सेवाएं देने से एडीए ने खड़े किए हाथ

जास, इलाहाबाद : सिविल लाइंस के संगम टावर में लिफ्ट का संचालन एडीए के लिए बवाल-ए-जान बन गया है। जो शुल्क इस भवन से प्राधिकरण को मिल रहा है। उसका दोगुना व्यवस्था पर खर्च हो रहा है। ऊपर से भवन में फ्लैट स्वामी यह शुल्क देने में भी आनाकानी कर रहे हैं। ऐसे में कई दिन से बंद पड़ी लिफ्ट चलाने से अब एडीए ने हाथ खड़े कर दिए हैं। बिल्डिंग में स्थित सभी सरकारी कार्यालयों के अधिकारियों के साथ बैठक कर प्राधिकरण ने भवन स्वामियों को अपनी सोसायटी बनाने का सुझाव दिया।

प्राधिकरण द्वारा बनाए गए व्यवसायिक भवन संगम टावर में 1984 से फ्लैट बिक गए थे। यहाँ कुल 133 प्रतिष्ठान हैं, जिसमें से 25 तो सरकारी कार्यालय हैं। ऐसे में यहाँ नियमित रूप से आने जाने वालों की संख्या भी हजारों में है। इस बहुमंजिला इमारत में आने जाने के लिए प्राधिकरण ने लिफ्ट लगवाई थी। जिसका संचालन भी लगातार प्राधिकरण ही करता आ रहा है। सन 1984 से लेकर अब तक लिफ्ट संचालन व अनुसूक्षण का खर्च तो बढ़ता गया, लेकिन इसके एवज में मिलने वाला शुल्क नहीं बढ़ रहा। ऐसे में यहाँ की लिफ्टें लगातार खराब हो रही हैं। पूर्व में भी कई बार प्राधिकरण ने यहाँ रहने वालों को खुद इसका संचालन संभालने का ऑफर दिया था। अब पिछले करीब एक सप्ताह से यहाँ की लिफ्ट खराब पड़ी है। यहाँ चल रहे सरकारी कार्यालयों को खासी तकलीफ उठानी पड़ रही है। इस समस्या का हल निकालने के लिए एडीए उपाध्यक्ष देवेन्द्र पांडेय और सचिव वंदना त्रिपाठी ने सरकारी विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि एडीए केवल भवन के अनुसूक्षण का जिम्मेदार है। लिफ्ट संचालन, सुरक्षा और स्टैंड आदि की सुविधाएँ सेवाओं की श्रेणी में आती हैं।

दैनिक जागरण 7/1/17